संख्याः 35 /XXVII(8)/NEGP-MMP/2010 दि0 26 अप्रैल, 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री अभिषेक सिंह,
निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
भारत सरकार, इलेक्ट्रिोनिक निकेतन, सी0जी0ओ0 काम्पेलक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली, 110011

विषयः– **प्रदेश के कोषागारों, उपकोषागारों, वाणिज्य कर कार्यालयो एवं वाणिज्य कर चैक पोस्ट हेतु स्थानापन्न (Alternative Connectivity) उपलब्ध कराने हेतु 124 VSAT क्रय किये जाने हेतु।**

महोदय,

वित्त विभाग के अधीन वाणिज्य कर विभाग का कम्प्यूटीकरण भारत सरकार के ई–गवर्नेन्स प्रोग्राम के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। उक्त कम्प्यूटरीकरण के तहत सभी कार्यालयों को SWAN के माध्यम से देहरादून स्थित डेटा सेन्टर से जोड दिया गया है। 01 अप्रैल, 2011 से प्रदेश के सभी 21 वाणिज्य कर कार्यालयो द्वारा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से सेन्ट्रल सर्वर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बोर्डर पर स्थित विभाग की 16 चैक पोस्टों को भी सेन्ट्रल सर्वर से जोडा जाना प्रस्तावित है। सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से व्यापारियों को ई–सर्विसेस दी जानी है। 01 अप्रैल, 2011 से ई–रजिस्ट्रेशन, ई–पेमेन्ट एवं ई–रिटर्न की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश के समस्त 29 कोषागार/उच्चीकृत कोषागारों (Treasuries/Sub Treasuries) को भी 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से SWAN के माध्यम से सेन्ट्रल सर्वर से जोड दिया गया है। उक्त सभी कोषागार/उपकोषागारों के द्वारा भी 01 अप्रैल, 2011 से वेब एप्लीकेशन के द्वारा सेन्ट्रल सर्वर से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रदेश के लगभग 1.50 लाख शासकीय कर्मचारियों एवं 1.20 लाख पेंशनरों का भुगतान कोषागारों द्वारा सेन्ट्रल सर्वर से कोर ट्रेजरी सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। उक्त सिस्टम को प्रदेश के तहसील/ब्लॉक मुख्यालय तक विकेन्द्रित कर अवशेष 57 उप कोषागारों (Sub Treasuries) के माध्यम से लागू किया जाना 01 जुलाई, 2011 से प्रस्तावित है।

आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार के ई–गर्वनेन्स कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) का वित्त विभाग राज्य में प्रमुख प्रयोगकर्ता है। राज्य में SWAN प्रोजेक्ट बी0एस0एन0एल0 (BSNL) की OFC से जुडे हुए है जो पहाड की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण प्रायः नेटवर्क डाउन/धीमा रहता है। जिससे कि वित्त विभाग के दोनो मिशन किटिकल एप्लीकेशन के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है।

राज्य में वित्त विभाग के कार्यालयो को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वायरलेस कनेक्टीविटी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव वित्त श्री आलोक कुमार जैन द्वारा श्री शंकर अग्रवाल अपर सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून से दूरभाष पर VSAT उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

प्रदेश के समस्त कोषागारों/उपकोषागारों तथा वाणिज्य कर कार्यालयो एवं चैक पोस्टो हेतु कुल 124 VSAT **(संलग्न सूची के अनुसार)** की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है कि उक्त VSAT DIT द्वारा देश के अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों (Inaccesable Areas) हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले टेण्डर के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं एन0आईसी0 से उक्त सभी कार्यालयों को आवश्यक बेन्डविर्थ (Bandwidth)उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करे। राज्य सरकार द्वारा उक्त VSAT क्रय हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान दोनो प्रोजेक्टो में प्राविधानित धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी,)
सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

पृ0प0संख्या /दिनाक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार।
2– प्रमुख सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड।
4– महा निदेशक, एन0आई0सी0, नई दिल्ली।
5– आयुक्त कर, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक आई0टी0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।